VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

ABHYAAS MAINS

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-II)/GENERAL STUDIES (Paper-II) (2423)

निर्धारित समय: **तीन घंटे** | अधिकतम अंक: **250**

Time Allowed: ***Three Hours*** | *Maximum Marks:* ***250***

सामान्य अनुदेश

इस प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका में 55+1 पृष्ठ हैं। प्रश्न-पत्र, क्यू.सी.ए. पुस्तिका के अंत में संलग्न है, जो अलग (वियोज्य) किया जा सकता है और उम्मीदवार परीक्षा के उपरांत अपने साथ ले जा सकते हैं।

रफ कार्य के लिए, इस पुस्तिका के अंत में खाली पृष्ठ दिया गया है।

पुस्तिका प्राप्त होने पर, कृपया यह जांच कर लें कि इस क्यू.सी.ए. पुस्तिका में कोई कमी न हो, फटा हुआ पृष्ठ न हो अथवा कोई पृष्ठ गायब न हो इत्यादि। यदि ऐसा हो, तो इसके बदले नई क्यू.सी.ए. पुस्तिका प्राप्त कर लें।

General Instructions

This Question-Cum-Answer (QCA) Booklet contains 55+1 pages. Question Paper in detachable form is available at the end of the QCA Booklet which can be taken away by the candidate after examination.

For rough work, blank page has been provided at the end of this Booklet.

On receipt of the Booklet, please check that this QCA Booklet does not have any shortcomings, torn or missing pages etc. If, so, get it replaced with a fresh QCA Booklet.

(उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा/To be filled by the Candidate)

पंजीकरण सं./Registration No. : 0763948

अभ्यर्थी का नाम/Name of Student : Shashank chauhan

माध्यम: हिंदी/अंग्रेजी
Medium: Hindi/English
Hindi

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-II)
GENERAL STUDIES (Paper II)

तारीख
Date
26/08/2023

केंद्र
Centre BHAI JOGA SINGH SCHOOL

निरीक्षक के हस्ताक्षर
Invigilator's Signature

VISIONIAS

	महत्वपूर्ण अनुदेश	Important Instructions
	उम्मीदवारों को नीचे उल्लिखित निर्देश सावधानी से पढ़ लेने चाहिए। किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने पर उम्मीदवारों को मिलने वाले अंकों में कटौती, उम्मीदवारी रद्द या आयोग के परवर्ती परीक्षाओं के लिए वर्जित करने इत्यादि के रूप में दण्डित किया जा सकता है।	**Candidates should read the undermentioned instructions carefully. Violation of any of the following instructions may entail penalty in the form of deduction of marks, cancellation of candidature, debarment from further Examination of the Commission etc.**
1	(क) अपना पंजीकरण सं. एवं अन्य विवरण केवल प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू.सी.ए.) में उम्मीदवार के लिए निर्धारित स्थान पर ही लिखें। (ख) इस पुस्तिका में अन्यत्र कहीं भी अपना नाम, पंजीकरण सं., मोबाइल नं., पता अथवा प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू.सी.ए.) संख्या न लिखें जिससे आपकी पहचान का खुलासा हो।	(a) Write your Registration Number and other details only in the space provided in the Question-Cum-Answer (QCA) Booklet for candidates. (b) Do not disclose your identity in any manner such as, by writing your Name, Registration number, Mobile number, Address, Question-Cum-Answer (QCA) Booklet No. etc. elsewhere in the Booklet
2	अपनी प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में कहीं भी प्रश्नों के वास्तविक उत्तर के अतिरिक्त कुछ न लिखें जैसे कि कोई कविता/दोहा, अभद्र या अपमानजनक अभिव्यक्ति इत्यादि और न ही कोई ऐसा चिन्ह/निशान बनाएं जिसका उत्तर से सम्बन्ध न हो।	Do not write in the QCA Booklet anything other than the actual answer such as couplet, obscene, abusive expression etc., nor put any sign/mark having no relevance to the answer.
3	परीक्षक को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी प्रार्थना/धमकी भरी बातें न लिखें।	Do not make any direct/indirect appeal/threat to the examiner.
4	उत्तर अस्पष्ट अथवा गंदी लिखावट में न लिखें। इस प्रकार के उत्तर का मूल्यांकन नहीं भी किया जा सकता है।	Do not write answers in bad/illegible handwriting. Such answers may not be evaluated.
5	उत्तर स्याही में ही लिखें। उत्तर लिखने के लिए पेंसिल का उपयोग न करें, हालांकि आरेख, चित्र इत्यादि बनाने के लिए पेंसिल का उपयोग किया जा सकता है।	Write answers in ink only. Do not use pencil for writing the answers. However, pencil may be used for drawing diagrams, sketches, etc.
6	प्रवेश पत्र में उल्लेख किए गए माध्यम के अलावा अन्य किसी माध्यम में उत्तर न लिखें। अधिकृत और अनधिकृत की मिली जुली भाषा का भी उपयोग न करें।	Do not write answers in medium other than the authorized medium in the Admission Certificate. Do not use mixed language either i.e. authorize and unauthorized media together for writing answers.
7	प्रश्नों के उत्तर ठीक उसके नीचे दिए गए निर्धारित स्थान पर ही लिखें। निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर लिखे गए उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।	Write answer at the specific space (right below the question) only. Answers written elsewhere at unspecified places in the booklet shall not be evaluated.
8	यदि आप अपने किसी उत्तर को रद्द करना चाहते हैं तो उसे पेन से काट दें तथा उस पर "रद्द" लिख दें, अन्यथा उसका मूल्यांकन किया जा सकता है।	If you wish to cancel any work, draw your pen through it and write "Cancelled" across it, otherwise it may be valued.

VISION IAS

कार्यालय के प्रयोग हेतु For Official Use	कार्यालय के प्रयोग हेतु For Official Use
परीक्षक के हस्ताक्षर Signature of Examiner(s)	

प्राप्तांक के विवरण (परीक्षक द्वारा भरा जाए)/ Marks Details (To be filled by the Examiner(s))

प्रश्न सं. Q. No.	अंक Marks		प्रश्न सं. Q. No.	अंक Marks	
1			**11**		
2			**12**		
3			**13**		
4			**14**		
5			**15**		
6			**16**		
7			**17**		
8			**18**		
9			**19**		
10			**20**		
उप-योग (A) Subtotal (A)			**उप-योग (B) Subtotal (B)**		
सकल योग (A+B) / GRAND TOTAL (A+B)					

VISION IAS

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
ABHYAAS MAINS

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-II)/GENERAL STUDIES (Paper-II) (2423)

निर्धारित समय: **तीन** घंटे Time Allowed: **Three** Hours	अधिकतम अंक: **250** Maximum Marks: **250**

प्रश्न-पत्र संबंधी विशेष अनुदेश

कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

*कुल **बीस** प्रश्न दिए गए हैं जो **हिंदी** और **अंग्रेजी** दोनों में छपे हैं।*

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्न संख्या 1 से 10 तक का उत्तर 150 शब्दों में तथा प्रश्न संख्या 11 से 20 तक का उत्तर 250 शब्दों में दीजिए।

प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखिए।

प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ भाग को पूर्णतः काट दीजिए।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions.

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.*

All questions are compulsory.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Answers to Questions No. 1 to 10 should be in 150 words, whereas answers to Questions No. 11 to 20 should be in 250 words.

Keep the word limit indicated in the questions in mind.

Any page or portion of the page left blank in the Questions-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

EVALUATION INDICATORS

1. **Contextual Competence**
2. **Content Competence**
3. **Language Competence**
4. **Introduction Competence**
5. **Structure - Presentation Competence**
6. **Conclusion Competence**

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS

1. उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से, चर्चा कीजिए कि पर्यावरणीय दबाव समूह भारत में पर्यावरण नीतियों के संबंध में सार्वजनिक भागीदारी और अनुक्रियाशीलता को कैसे बढ़ाते हैं। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
With suitable examples, discuss how environmental pressure groups enhance public participation and responsiveness with regard to environmental policies in India. (Answer in 150 words) 10

अभ्यर्थियों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

दबाव समूह से आशय किसी निश्चित समूह द्वारा अपने निहित उद्देश्यों की पूर्ति कराने को संदर्भित करता है।

जो दबाव समूह पर्यावरणीय उद्देश्यों को उठाते हैं उन्हें पर्यावरणीय दबाव समूह कहते हैं

(उदा०) चिपको मूवमेंट
नर्मदा बचाओ आंदोलन

पर्यावरण नीतियों की भागीदारी में दबाव समूह

- उत्तराखंड में पेड़ों के अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए 'चिपको मूवमेंट' चलाया जाना
- 'भोपाल गैस त्रासदी' से भोगित नागरिकों के अधिकारों के दिलाने में EPA Act 1986 का अधिनियमित करना
- भारत में चाईना की ड्रेगन में तीव्र

शिकार के कार्यों में दबाव समूह द्वारा उठाया गया

(उदा०) प्रोजेक्ट टाइगर 1973

- प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालीम अली द्वारा पक्षियों के संरक्षण के लिए सरकार पर दबाव

  (उदा०) बॉम्बे नैचुरल सोसाइटी से भरप के पक्षियों का संरक्षण

- बाध्य बनाते हैं नदी प्रवाह तथा जानवरों के प्राकृतिक स्थान को छिनने के दबाव में

  (उदा०) नर्मदा बचाओ आंदोलन, केन बेतवा परियोजना के विरुद्ध प्रदर्शन

- 'चीता संरक्षण' के चलाये अभियान को विभिन्न दबाव समूहों द्वारा विरोध

  (उदा०) भारत की क्षेत्रीय विविधता वाले जानवरों पर विपरीत प्रभाव

हालांकि दबाव समूहों के समक्ष कुछ चुनौतियां देखने को मिलती हैं जैसे विदेशी सहायता के आधार पर परियोजना का विरोध करना — अत्यधिक सक्रिय व्यवहार — सरकार द्वारा 'दबाव समूह' से संबंधित स्पष्ट विचार लाने की आवश्यकता है

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

2. हाल ही में, उच्चतम न्यायालय द्वारा सेक्स वर्क को एक 'पेशे' के रूप में स्वीकार किया जाना, भारत में सेक्स वर्कर्स के लिए बुनियादी अधिकार और समानता सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम है। परीक्षण कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

The recent acknowledgment of sex work as a 'profession' by the Supreme Court is merely the first step in ensuring basic rights and equality for sex workers in India. Examine. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सेक्स वर्करों की संख्या के संबंध में स्पष्टता की कमी का अभाव है जिसका मुख्य आधार पेशे को छुपाने का कारण है।

सेक्स वर्कर्स के संबंध चुनौतियां

◎ सामाजिक स्वीकृति का अभाव

(उदा०) अनु 21 के तहत गरिमा के जीवन से वंचित

◎ नियोजन क्षेत्र में भेदभाव तथा कार्य के निकलते हेतु विवाद

(उदा) अनु० 16 के नियोजन का उल्लंघन

◎ स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं तक पहुँच का अभाव

(उदा) HIV के प्रति सुभेद्य होते

के कारण, SC द्वारा अनु० 19(g) के तहत घूमने की स्वतंत्रता पर रोक
(स्वास्थ्य आधार के कारण)

© नौकरी, आवास तथा सामाजिक गतिशीलता को प्राप्त करने में चुनौतियाँ

(उदा०) अनु० 19 के तहत कार्य के अधिकार का विफल

हालिया कदम | © SC द्वारा पेशे के रूप में स्वीकृत
© कुछ एजेंसियों द्वारा सेक्स वर्कर्स को काम रखने पर ~~रोक~~ दिया गया (समानता के सिद्धांत के कारण

आगे की राह → नियोजन पर भेदभाव को रोका जाना चाहिए
→ 'HIV टेस्ट' की जाँच के बाद
↓
शिक्षा, विवाह जैसी चीज़ों को ही चुनने संबंधी प्रतिबंधों को लगाना
राज्य द्वारा बल प्रदान करने की जरूरत

सेक्स वर्कर्स भी नागरिक हैं अतः उन्हें सभी नागरिकों अधिकारों तक पहुँच प्रदान करनी चाहिए

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

3. भारत में नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने और कानूनी जागरूकता फैलाने में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSAs) द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Discuss the role played by District Legal Services Authorities (DLSAs) in providing free legal aid and disseminating legal awareness in India. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व के रूप में अनु. 39 (A) के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने की वकालत की गयी है।

— 1987 ई. में 39 (A) को धरातल पर लाने के लिए 'DLSA's' का गठन किया गया था

DLSA's द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका

(i) आम नागरिक तक कानून की पहुँच को स्थापित करना

उदा० ADR रिपोर्ट भारत में दलित आदि के अधिकार 50% से ज्यादा मामले दर्ज किये नहीं जाते

(·) लंबित केसों की संख्या को कम करना

उदा० 3.5 करोड़ मामले भारतीय

न्याय प्रदान में लंबित

- समाजिक 'अन्याय' कोप रोकना

(उदा) गांवों में सूदखोर द्वारा उच्च ब्याज पर ऋण देना

थोड़े पैसों में जमीन लिखवानी जैसी घटनाएं

- समाज के सुभेद्य वर्गों तक 'कानून' की पहुँच को आसान बनाना

(उदा) NCRB के अनुसार 1/3 rd से ज्यादा महिला हिंसा के मामले कोर्ट तक नहीं पहुँचते

DLSA's के समक्ष चुनौतियाँ → अवसंरचना का अभाव

- न्याय की बाधाकारी प्रकृति
- लोगों तक जागरूकता का अभाव
- संबंधित पार्टी के किसी एक पक्ष द्वारा DLSA's का समर्थन न करना
- प्रबंधन एवं स्टाफ (रिक्तता) संबंधी समस्याएं

प्रौद्योगिकी का उपयोग, अवसंरचना में निवेश तथा जागरूकता प्रदान कर "द्वार पर न्याय" की पहुँच को पाया जा सकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

4. "कुछ लोगों के हाथों में शक्ति के संकेंद्रण के कारण, कॉलेजियम प्रणाली अपनी ही सफलता का शिकार हो गई है, जिससे इसकी वैधता पर सवाल उठने लगे हैं।" टिप्पणी कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
"The collegium system has become a victim of its own success, with the concentration of power in the hands of a few, leading to questions about its legitimacy." Comment. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारतीय न्यायिक प्रणाली में 'कॉलेजियम व्यवस्था' जजों की भर्ती, उनके स्थानांतरण तथा उनके पदोन्नति के मामलों को लेकर सरकार से सिफारिश करती है।

कालेजियम प्रणाली का स्वरूप

S.C
- (CJI + 4 अन्य वरिष्ठ सदस्य)
- HC के जजों की संख्या के संदर्भ में (CJI + 2 वरिष्ठ सदस्य)

HC collegium
(CJ + 2 वरिष्ठ सदस्य)

कालेजियम के समक्ष चुनौतियाँ

- प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ
  उदा० जज, किसी अन्य जज की नियुक्ति नहीं कर सकता

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

④ विश्व के किसी अन्य विकसित या विकासशील देशों में ऐसी परंपरा का न पाया जाना

⑤ कॉलेजियम के निर्णयन का प्रकटीकरण न होना

(उदा) 'Anonymity' के सिद्धांत का पालन करता है

⑥ हालिया दिनों में अप्रचलित निर्णयन का होना

(उदा) तमिलनाडु HC (Chief Justice) का मेघालय HC में ट्रांसफर होना
(13 जज वाली कोर्ट से 2 जज वाली कोर्ट में ट्रांसफर)

आगे की राह → 'NJAC' जैसे प्रावधानों को कुछ मूलभूत परिवर्तनों के साथ लागू करना

→ 'कालेजियम' के निर्णयों का प्रकटीकरण करना

→ 'Timebound' मैनर में वेबसाइट पर अपने निर्णयों को डालना

भारतीय न्यायिक प्रणाली, भारतीय राजनीति का मजबूत स्तंभ है जो देश में 'लोकतंत्र' को बनाए रखने में मदद करती है, मगर ही इसको अपनी भर्ती संबंधी प्रक्रिया में सुधार करने की

5. "सिविल सेवा सुधारों को वर्तमान दौर की चुनौतियों से निपटने के लिए भर्ती और मानकीकृत प्रशिक्षण से आगे बढ़ाया जाना अनिवार्य है।" विश्लेषण कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
"Civil services reforms must go beyond recruitment and standardised training to cope with the present day challenges." Analyse. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारतीय सिविल सेवा 'वेबेरियन नौकरशाही' के उस सिद्धांत पर आधारित है जहाँ परीक्षा के आधार पर पदोन्नति, श्रम विभाजन तथा कठोर निर्णयन /अनुशासन जैसे सिद्धांत पाए जाते हैं।

नौकरशाही से संबंधित चुनौतियाँ

- 'Ivory Tower' Approach की धारणा का होना
  - उदा० सामाजिक धरातल से दूर रहना
- 'नौकरशाही Inertia' की स्थिति का होना
  - उदा० नियमों को साध्य सिद्ध करना
- रेड टेपिज्म, भ्रष्टाचार को बढ़ावा
  - उदा० नियमों में Loophole का फायदा उठाना
- सेवा के 'प्रति प्रतिबद्धता' जैसे मूल्यों की कमी का होना

(उदा०) छत्तीसगढ़ में DM द्वारा गरीब का थप्पड़ खवाना धरपाना। IAS couple द्वारा कुत्तों को घुमाने के लिए 'Stadium' का प्रयोग करना

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भर्ती और मानकीकृत प्रशिक्षण के आगे की जरूरत

(a) संवेदनात्मक नौकरशाही के मूल्य को बढ़ावा देना

(उदा०) आर्मस्ट्रांग पेम द्वारा 100 km सड़क का निर्माण करना, बिना किसी राजकीयकोष की सहायता के

(b) 'code of ethics' को लागू करने की आवश्यकता

(c) 'मिशन कर्मयोगी' जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा

(d) 'Elton Mayo's' experiment के तहत उनके भत्तों आदि में वृद्धि करना ताकि वे जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता दिखा सके

(e) उनके द्वारा जनता को सेवाप्राप्तकर्ता की जगह 'Master' की तरह देखना (Democracy ↓ जनता ही मालिक है)

2nd ARC द्वारा संवेदनात्मक नौकरशाही के मूल्यों को अपनाने पर जोर दिया गया है। PM मोदी द्वारा खुद को 'प्रधान सेवक' जैसी भावना का सिविल सेवा में अनुसरण करना चाहिए

6. सामाजिक प्रभाव बॉण्ड्स जैसे परिणाम-आधारित वित्त मॉडल में वास्तविक रूप से परिवर्तन लाने और बड़े पैमाने पर सामाजिक-आर्थिक प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता विद्यमान है। विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Outcome-based finance models such as social impact bonds have the potential to truly catalyse change and deliver socio-economic impact at scale. Discuss. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

सामाजिक प्रभाव बाण्ड्स से आशय ऐसे निवेश के साधनों से है जो सामाजिक स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं।

(उदा) ग्रीन बांड

सामाजिक प्रभाव बांड के महत्व

सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

① यह नकारात्मक Externalities से होने वाले परिणामों के समाधान के तौर पर देखा जाता है।

② जलवायु परिवर्तन से होने वाले अव्यवस्था तथा जल ह्रास के मुद्दों से संबंधित एक सकारात्मक निवेश के रूप में

(उदा) Climate Resilient Infra Bond

- महिला उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने संबंधी-

उदा० नन्ही कली (Mahindra Tec education)

- "वनारोपण" के तहत आदिवासी अधिकारों के संरक्षण में

उदा० REDD+, CAMPA FUND जैसे में निवेश

- जनजातीय अधिकारों के संरक्षण तथा उनके आर्थिक हितों के लाभ पाने के संदर्भ

उदा० TRIFED द्वारा 'जनजातीय उत्पादों'

सामाजिक प्रभाव बांड से संबंधित चुनौतियाँ

- उच्च लाभ नहीं (निवेशकों को उच्च आय की प्राप्ति न होना)
- मार्केट में इन 'बांडों' के प्रति कम आकर्षण होना
- जागरूकता का अभाव

(सामाजिक प्रतिबद्धताओं के लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाने की दशा में — उदा० वनीकरण (Campa fund)

सरकार द्वारा CSR जैसी गतिविधियों तथा चेतावनी जैसे विधि से 'सामाजिक प्रभाव बांड' के प्रोत्साहन को बढ़ावा देना चाहिए।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

7. प्रत्येक वर्ष ग्रेजुएट होने वाली और कार्यक्षेत्र में प्रवेश करने वाली महिलाओं की संख्या के मध्य का व्यापक अंतराल एक गंभीर समस्या है जिसे हल किए जाने की आवश्यकता है। भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

The wide gap between the number of females graduating every year and those entering the workspace is an issue of paramount importance that needs to be addressed. Discuss in the context of India. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

PLFS सर्वेक्षण के हालियाँ आँकड़ों के मुताबिक भारत में 2020-21 में महिला श्रम बल की दर 32% के आसपास है, जो 2004-05 में 43-44% के स्तर पर थी।

हालांकि इस दौरान Gross enrolment Ratio में महिलाओं की संख्या पुरुषों से आगे निकल गयी है।

ग्रेजुएट की संख्या में वृद्धि तथा कार्यक्षेत्र में कमी → जैसे 'Divergence' के कारण

① 'Glass ceiling' की उपस्थिति का होना
(उदा०) योग्यता होने के बावजूद समकक्षी पुरुष के पद तक न पहुँचना

② कार्यस्थल पर शोषण संबंधी समस्या
(उदा०) NCRB आंकड़ों के मुताबिक कार्यस्थल पर शोषण की संख्या में

पिछले वर्ष की तुलना में ~16% की वृद्धि देखी गयी

◉ 'वेतन gap" की समस्या का होना

(उदा) विश्व असमानता रिपोर्ट → (महिलाओं को पुरुष समकक्षी की तुलना में 20% कम वेतन प्राप्त)

◉ पुरुषों की आय में वृद्धि न होना (परिवार)

(उदा) तत्पश्चात महिला द्वारा घरेलु कार्यों को किया जाना

◉ "Pink collar" Job की उपलब्धता न होना

(उदा) यह महिलाओं के 'Skill mismatch' वाली अवस्थाओं को दिखाता है

उपाय → 'STEM' क्षेत्रों में महिला भागीदारी को बढ़ावा देना

→ 'POSH 2013" के माध्यम से शोषण को अनुकूलित करने पर बल

→ 'Gender Pay Audit" को नियमित अंतराल पर करना

STEP (Skill cum employment Progm) को बढ़ावा देना

WEF की रिपोर्ट के अनुसार यदि महिला श्रमबल में भागीदारी करती है तो यह अर्थव्यवस्था में ~24% की वृद्धि को हासिल कर सकता है

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

8. भारत में सामाजिक-आर्थिक नियोजन के लिए एक अद्यतित और कार्यात्मक नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) अनिवार्य है। देश में CRS प्रणाली में सुधार हेतु केंद्र सरकार के हालिया कदम के आलोक में चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

An up to date and functional Civil Registration System (CRS) is essential to the socio-economic planning in India. Discuss in the light of the recent move of the Central government in revamping the CRS system in the country. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

कार्यात्मक नागरिक पंजीकरण से आशय नागरिकों की मूलभूत जानकारियों को एकत्र करने से है।

CRS का महत्व:-

- Outcome based polices के निर्माण में
- संसाधनों के इष्टतम प्रयोग में
- विसंगतियों के उन्मूलन में
- उपयोगकर्ता वर्ग की विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए

CRS से संबंधित चुनौतियाँ

- वैज्ञानिक कागज, डाटा / आंकड़ों का अभाव
- आंकड़ों का प्रयोग लोगों की अभिवृत्तियों को बदलने में
- राजनीतिक प्रचार के लिए इन आंकड़ों का उपयोग

आगे की राह — पारदर्शी सिस्टम को बनाना

- नियामक निकाय पर जोर
- डाटा प्रोटेक्शन को बढ़ावा

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

9. यदि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) को वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं के साथ समायोजित होना है तो इसमें सुधार के प्रमुख क्षेत्र कौन-से होंगे? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

What are the key areas of reform if the International Monetary Fund (IMF) has to align with the current economic realities? (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत सुधार के तौर पर 'IMF' संस्थान की नींव रखी गयी थी जिसका प्रमुख उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था के अनुकूल माहौल को बनाए रखना है।

IMF के निहित चुनौतियाँ

(a) पश्चिमी देशों का प्रभुत्व

उदा० IMF का अध्यक्ष हमेशा यूरोपीय तो वहीं वर्ल्ड बैंक का अमेरिकी

(b) कोटा आधारित ~~अर्थव्यवस्था~~ वोटिंग व्यवस्था

उदा० वैश्विक देशों की अर्थव्यवस्था के अनुरूप निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करना

(c) वैश्विक सुधारों को सिर्फ पश्चिमी

देशों की नजरों से देखना
(उदा.) रूस-यूक्रेन युद्ध में रूस पर प्रतिबंध, जबकि इस प्रतिबंध ने वैश्विक खाद्य व्यवस्था के समक्ष खतरे को नजरअंदाज करना

◎ सुधारों का अलोकतांत्रिक स्वरूप
(उदा.) सुधारों के लिए 85% वोटिंग की आवश्यकता जबकि अकेले अमेरिका का आरक्षण → 28% (यानि US को अप्रत्यक्ष रूप से वीटो प्रदान करना

सुधार के प्रमुख क्षेत्र
◎ 'कोटा' आधारित व्यवस्था का पुनर्गठन करने पर जोर
◎ सुधारों के लिए 75% (उच्च पक्ष के वोटों को कम करना)
◎ अध्यक्षों के 'चुनाव' में विश्व के अन्य देशों को भी मौका प्रदान करना
◎ 'नीतियों के निर्माण' को सदस्य देशों के अनुरूप चार्टर बनाकर लागू करना
◎ अर्थव्यवस्था राशि सहायता में देशों पर सख्त सुधारों को लागू न करना

IMF में सुधार वैश्विक अर्थव्यवस्था की माँग जहाँ संरक्षणवाद, वैश्वीकरण की दिशा में बाधक बन रहा खड़ा है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

10. हाल के वर्षों में, पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंध भू-राजनीति के दायरे से आगे निकलकर भू-अर्थशास्त्र के आयाम तक पहुंच गए हैं। विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

In recent years, India's relationship with West Asia has evolved from the confines of geopolitics to expanse of geoeconomics. Discuss. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत तथा पश्चिम एशिया के मध्य ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संबंध रहे हैं जिसका आधार 'भारतीय डायस्पोरा' के माध्यम से लगाया जा सकता है।

(भू-राजनीति के संबंध)

- OIC में भारत को निमंत्रण बुलावा
- UAE, सऊदी के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी
- पश्चिमी एशिया के अधिकांश देशों द्वारा भारतीय PM को सम्मान। UAE - 'नागरिक सम्मान'

भू-अर्थशास्त्र

- भारत अपनी 80% ऊर्जा आयात करता है

जिसका मुख्य भाग पश्चिमी देशों है

① पश्चिमी एशिया की खाद्य सुरक्षा का मुख्य आधार — भारतीय निर्यात (गेहूं, चावल)

② 'Remittances' का एक बड़ा भाग भारतीय अर्थव्यवस्था में पश्चिमी देशों के प्राप्त होता है।

पश्चिमी एशिया देशों के संबंधों में चुनौतियाँ

— OIC में 'कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान द्वारा उठाया जाना'

— कतर में भारतीय नौसैनिकों की गिरफ्तारी

→ भारतीय प्रवासियों पर होने वाले हमले

आज एबार्ड, FTA आदि आपसी बातों से भारत पश्चिमी एशिया के साथ अपने संबंधों को और मजबूत कर रहा है।

11. हितधारकों को नवाचार और प्रभावशीलता में वृद्धि हेतु प्रेरित करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की भूमिका महत्वपूर्ण है। टिप्पणी कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

The role of the Competition Commission of India (CCI) is significant in furthering healthy competitiveness aimed at inspiring stakeholders to innovate and augment effectiveness. Comment. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, 2002 के अधिनियम से औद्योगिक क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिपादित किया गया था।

CCI की नवाचार और प्रभावशीलता बढ़ाने में भूमिका :-

(1) 'अस्वस्थ' कार्य संस्कृतियों पर प्रतिबंध लगाना

(उदा) 'Google App Store' पर कोणी क्रम की महत्ता के कारण प्रतिबंध लगाना

(2) बाजार में होने वाले 'मर्जर' की संस्कृति को रोकना

(उदा) 'Amazon - Future group' के मर्जर को रोकना, stakeholder की शिकायत की तरह के

Ⓞ नवाचारात्मक बाजार गतिविधियों को रोकने में
(उदा) Amazon, flipkart में होने वाली Flash sale" के संबंध में जवाब मांगना

Ⓞ कंपनी के "कोई अन्य ऑपरेटर" तथा प्रबंधन की गतिविधियों में हस्तक्षेप करना
(उदा) उदय शंकर रघु (Yes Bank")

Ⓞ 'IPR' से संबंधित उल्लंघन में उपभोक्ता विभाग को सूचित करना

Ⓞ अवैध स्टॉकिंग तथा नवाचारात्मक मार्केटिंग की स्थिति पर अंकुश लगाना

Ⓞ 'इन्वेंटरी' से संबंधित हेरफेर कर, उत्पादों के अवमूल्यन को रोकना

CCI से संबंधित चुनौतियाँ।

Ⓞ CCI के निर्णयनों को UK की CCI की तरह पंजीकृत करने का अधिकार

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

प्राप्त न होना

② IPR के संबंधित मामलों में प्रत्यक्ष रूप से निर्णय न ले पाना

④ CCI के पक्ष में राजनीतिकरण की समस्या का होना

⑤ CCI द्वारा कंपनी के कार्यों पर तत्कालिक रूप से रोक लगाने का अधिकार नहीं

⑥ US की CCI की तरह निवारक व निगरानी दोनों तरह के अधिकारों का न होना

आगे की राह → CCI के अधिकारों को US, UK के CCI की तरह बढ़ाना

↓ CCI के सदस्य तथा अध्यक्षों के चुनाव में राजनीतिकरण को बढ़ावा न देना

↓ IPR से संबंधित शक्तियों को विस्तृत करना

CCI भारतीय अर्थव्यवस्था में स्पर्धात्मक माहौल को बनाए रखने में एक प्रमुख 'प्रहरी' बन सकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

12. "पेड न्यूज का खतरा अक्सर चुनावों के दौरान अपना भयावह रूप दिखाता है।" भारत में पेड न्यूज को एक चुनावी अपराध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
"The menace of paid news often rears its ugly head during elections." Discuss the need for making paid news an electoral offence in India. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

"पेड न्यूज" से आशय मीडिया चैनलों द्वारा ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जहाँ एक विशिष्ट एवं लक्षित अभिवृत्ति को जनता के समक्ष थोपा जाता है।

पेड न्यूज और चुनावों का संबंध

① पेड न्यूज के माध्यम से social engineering कर वोटर की अभिवृत्ति परिवर्तन

(उदा०) हिलेरी-ट्रंप चुनाव में हिलेरी के "mails" को प्रचारित करना

② चूंकि 'स्वतंत्र एवं निष्पक्ष' चुनाव 'Basic structure' का आधार है लेकिन 'Paid News' पारदर्शिता को छुपाने का कार्य करता है।

③ 'फेक न्यूज' तथा 'उड़ने वाली' खबरों के माध्यम से सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना

उदा० दिल्ली 2020 दंगों के दौरान पेड न्यूज़ों का चलना

② 'सच्चाई' से समाज को दूर ले जाना

(उदा०) नकली 'Exit Poll' से दिखाना

③ किसी विशिष्ट नेता या प्रतिद्वंद्वी की छवि को खराब करना

④ समाज में चल रहे ज्वलंतशील मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए

(उदा०) 'अडानी' overprice stock में अडानी का विभिन्न चैनलों द्वारा Interview करना

| पेड न्यूज को अपराध बनाने की आवश्यकता |

| पक्ष में तर्क |

- मूल मुद्दों के भटकाव की स्थिति में कमी होगी
- 'Deterrence' फैक्टर के चलते मुद्दों को जानबूझकर

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

जवाबदेहशील भी बनाया जाएगा

- 'निष्पक्ष चुनाव' की तरफ बढ़ने का संकेत होगा
- सामाजिक अभिवृत्ति तथा अनुनय के बदलने के प्रयासों में कमी आएगी
- लोगों द्वारा बिना किसी पूर्वाग्रह के समाज में व्यभिचार करने पर जोर दिया जाएगा

विपक्ष में तर्क

- यह 'प्रेस' के लोकतंत्र में 'चौथे स्तंभ' की भूमिका को खंडित कर सकता है।
- राजनेताओं तथा पूंजीपतियों पर मीडिया को दबाव डालने का प्रयास किया जाएगा

'सभी तक खबर के पहुंच' की संभावनाओं में नाराजगी

मीडिया का कार्य कमजोर तबके के लोगों की आवाज बनना है जिसे पेड न्यूज जैसी कुछ विसंगतियों में सुधार करके किया जा सकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

13. भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में, न्यायालयों द्वारा उद्धृत 'अनिवार्यता के सिद्धांत' पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Discuss the 'Doctrine of Essentiality' referred to by the courts in the context of religious practices in India. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

धार्मिक प्रथाओं में 'अनिवार्यता के सिद्धांत' से आशय धार्मिक संदर्भ में उन मूल परंपराओं को पहचानने से है, जिनके बिना धर्म की प्रवृत्ति में बदलाव आ सकता है।

न्यायालयों द्वारा उद्धृत अनिवार्यता का सिद्धांत

- शिरूर मठ केस (1954) :- सर्वप्रथम 'अनिवार्यता के सिद्धांत की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस केस में की गई

- शाह बानो केस (1986) :- तलाक-ए-बिद्दत को इस्लाम का मूल भाग मानने में S.C द्वारा दिया गया निर्णय
  (2010) 'तलाक' को अनिवार्य सिद्धांत का भाग नहीं माना

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

बाबरी मस्जिद विवाद (1994) :- 'नमाज पढ़ने की अवस्था' इस्लाम का मूल भाग है कि नहीं पर प्रश्न

↓

'नमाज़' को मस्जिद में पढ़ने को इस्लाम का अनिवार्य भाग नहीं माना

सबरीमाला विवाद (2019) :- मंदिर में महिला का प्रवेश, तत्कालीन प्रभु की अराध्यता का भाग है या नहीं

↓

(अभी इस प्रश्न पर निर्णय आना बाकी है).

'अनिवार्यता' के सिद्धांत' संबंधी चिंताएं

- 'धर्म', धार्मिक लोगों का आधार, न्यायालय यह जानने में विफल है कि क्या अनिवार्य है और क्या नहीं'

(उदा०) अनु. 26 के अंतर्गत, धार्मिक मामलों के प्रबंध का अधिकार

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

- धार्मिक मामलों में न्यायालय की विशेषज्ञता का अभाव
- 'अनिवार्यता का सिद्धांत' → 'Judicial over reach' का उदाहरण
- विभिन्न धार्मिक गुरुओं द्वारा न्यायालय से उन्हें या धर्म विशेषज्ञ को अनिवार्यता के सिद्धांत के अधिकार देने की मांग

आगे की राह

- न्यायालय द्वारा परंपराओं को मानवता के आधार पर देखना
- → सर्वप्रथम धर्म गुरुओं को परिवर्तन करने को कहना
- ↓ 'last lasting Resort' की ही स्थिति में न्यायालय द्वारा अनिवार्यता का सिद्धांत देना

भारतीय संविधान में अनु. 25 तथा अनु 26 दोनों के द्वारा धर्म से संबंधित अधिकार दिए गए हैं, न्यायालय को आवश्यकता है इनमें समन्वय को स्थापित करने की।

14. प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सरकार के आकार को सीमित करने की तत्काल आवश्यकता है। क्या आप सहमत हैं? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

As per the recently released report of the Economic Advisory Council to the Prime Minister (EAC-PM), there is an urgent need to limit the size of the government in India. Do you agree? (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

PM की आर्थिक सलाहकार परिषद से आशय, आर्थिक मामलों पर प्रधानमंत्री को राय प्रदान करने से संबंधित है।

91 वे संविधान संशोधन अधि० के तहत सरकार के आकार को लोकसभा की संख्या के 15% तक सीमित करने का प्रावधान किया गया है।

सरकार के आकार को सीमित करने के पक्ष में तर्क

(i) यह केंद्र के संसाधनों पर उच्च व्यय को बनाता है।

(उदा०) पेंशन, तनख्वाह, सुरक्षा, निवास जैसी सुविधाएँ

(ii) यह सरकारी की निर्णय संबंधी प्रक्रिया को धीमा करता है

(उदा०) वर्ष (1978—1980) तक के गठबंधन भारत में निर्णय लेने की क्षमता में ह्रास

© यह दल-बदल जैसे घटनाओं में वृद्धि का कारक बनता है।

उदा० मंत्री या उपमंत्री पद न मिलने पर दूसरे दल में जाने संबंधी घटनाएं

⊙ 'PM' तथा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत

अत्यधिक संख्याओं की मांग पर बल नहीं देते हैं।

⊙ सरकार के राजस्व व्यय भार में कुप्रभाव होगा

⊙ पोर्टफोलियों का प्रयोग कर एक मंत्री को अधिक विभाग देने की स्थिति संविधान में पहले से मौजूद होता

विपक्ष में तर्क :- ⊙ यह छोटे दलों तथा उनके प्रतिनिधित्व को सरकार में सीमित करेगी

⊙ यह 'कार्यपालिका' के वर्चस्व को बढ़ावा

*उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

देगी

① जनता तथा नेता के बीच आत्मीयता के स्तर पर ह्रास होगा

② सरकार को राय प्रदान करने वालों में कमी आएगी (जिससे निर्णयन में कुशलता बाधित होगी)

③ सरकार के 'व्यक्तिवादी' स्वरूप को बढ़ावा मिलेगा

④ लोकतंत्र के समान प्रतिनिधित्व का ह्रास होगा जहाँ अन्य सदस्य की बातों पर यदि बल नहीं दिया जाएगा

आगे की राह

→ एक 'विशिष्ट प्रकाशन' के माध्यम से सरकार के सही आकार को जानने का प्रयास करना

→ 'उपमंत्री' जैसे पदों को कम करने पर बल

↓ 'GOM' को बढ़ावा देना

संसदीय राजव्यवस्था में 'सरकार' प्रमुख होती है जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है अतः राजस्व कार्यकुशलता को देखते हुए ही सुधार पर बल देना चाहिए।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

15. इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस (IoE) योजना की कल्पना भारत में उच्चतर शिक्षा के 'विश्व स्तरीय' केंद्र विकसित करने के लिए की गई थी, लेकिन छह साल बाद भी, यह अभी तक गेम चेंजर नहीं बन पाई है। विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

The Institutions of Eminence (IoE) scheme was conceived to develop 'world-class' centres of higher education in India but six years later, it is yet to become the game changer it was intended to be. Discuss. (Answer in 250 words) 15

*उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

'इंस्टीट्यूशंस आफ एमिनेंस' का उद्देश्य शिक्षा के विश्व स्तर को प्राप्त करने तथा शेष कालेजों के लिए मानकों के तौर पर स्थापित करना था।

'IOE' में शामिल संस्थान

IIT दिल्ली, IIT बंबई, IISC बैंगलोर, जियो कालेज — etc)

IOE का महत्व :

→ विश्व की शीर्ष 100 संस्थानों में भारतीय कालेजो की वृद्धि करना

→ 'Patent', 'Research General' की संस्कृति को कालेजो में आत्मसात कराना

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

- शोध तथा उद्योग के बीच के गैप को कम करना

(उदा०) 'PMRF' के तहत उच्च राशि प्रदान कराना (Phd scholarship)

- अवसंरचना तथा प्रयोगशालाओं की तुलना पश्चिमी विश्वविद्यालयों के बराबर स्थापित करना

- विदेशों के छात्रों को इन संस्थानों की तरफ आकर्षित करना

(उदा०) QS रैंकिंग में विदेशी छात्रों का घटक महत्वपूर्ण कोटे को रेखांकित करता है।

IOE से संबंधित चुनौतियाँ

- कुछ ऐसे कालेजों को चिन्हित करना जो अभी तक खुले भी नहीं है।

(उदा०) जिओ कालेज

- वित्त की अपर्याप्तता

(उदा०) प्रत्येक कालेज को 1000 करोड़ की राशि प्रदान करने केवल

अक्षमता

(1) IOE संबंधित स्पष्ट 'Blueprint' का न होना

(2) IOE के संबंधित उद्देश्यों को प्राप्त करने संबंधी लक्ष्यों का भी न होना

(3) निजी तथा सरकारी संस्थानों में समन्वय जैसे मुद्दों का होना

आगे की राह

→ 'समयबद्ध' उद्देश्यों को IOE के तहत शामिल करना

→ 'IOE' में शामिल संस्थानों के चयन को पारदर्शी बनाना

- 'CSR' फंडों के माध्यम से IOE के वित्तपोषण को बढ़ावा देना

- 'PPP' के माध्यम से निजी संस्थानों को IOE की तरफ आकर्षित करना

'IOE' निश्चित ही AI, मशीनलर्निंग तथा औद्योगीकरण 4.0 के लक्ष्यों की प्राप्ति करने में महत्वपूर्ण घटक साबित हो सकता है।

www.visionias.in

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidate must not write on this margin

16. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) नवोन्मेषी और सुविधाजनक सार्वजनिक सेवाओं की अनुमति देता है, समावेशन या पहुंच संबंधी बाधाओं को दूर करने में मदद करता है तथा रियल-टाइम डेटा की मदद से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाता है। उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Digital Public Infrastructure (DPI) allows for innovative and convenient public services, help overcome inclusion or accessibility barriers, and increase transparency and accountability with real-time data. Discuss with examples. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से आशय, लोक सेवाओं संबंधी संस्थानों के 'डिजिटलीकरण' स्वरूप को प्रदर्शित करता है।

DPI का महत्व

• नवोन्मेषी और सुविधाजनक सार्वजनिक सेवा

• मुहैया तथा नागरिकों तक संस्थान की पहुँच स्थापित करना
उदा० IRCTC मैसेज प्रणाली

• 'On Tap' जानकारी की व्यवस्था का होना
उदा० 'PM KISAN' जैसी लाभार्थियों द्वारा अपनी किश्तों को देखना

• 'e-pay" जैसी सुविधाओं का होना
उदा० किसी विशिष्ट

इलेक्ट्रानिक उपकरण की आवश्यकता का न होना

समावेशन की व्यवस्था :

- दूर दराज (last mile) व्यक्ति तक पहुँच को स्थापित करना
- Digital Divide जैसी समस्याओं को भी overcome करना
- सूचना प्राप्त करने संबंधी किसी विशिष्ट आय / कागजों का अभाव
  - (उदा॰) Digilocker

पारदर्शिता और जवाबदेहिता

- 'UID' तथा 'GPS' के माध्यम से सेवाओं को जोड़ना
- सूचनाओं के एकत्रीकरण से जवाबदेहिता को सुनिश्चित करना
  - (उदा॰) DBT, Receipt व्यवस्था
- लाभार्थियों की संख्या तथा विश्लेषण

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए Candidate must not write on this margin

को अनुकूल बनाने की आवश्यकता

DPI से संबंधित चुनौतियाँ

- भारत में डाटा रेगुलेशन से संबंधित कानून का अभाव
- साइबर हमलों के प्रति संस्थानों का सुभेद्य होना
  - उदा० आरोग्य सेतु ऐप से डाटा चोरी होना
- डिजिटल विभाजन की समस्या
  - उदा० भारत की सिर्फ 27% महिलाएं कार्यों के उद्देश्य से इंटरनेट का उपयोग करती हैं।

आगे की राह

→ डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा (PMGDISHA)

→ डिजिटल विभाजन की समस्या को दूर करना (भारतनेट, PM वाणी)

↓ डाटा नियामक निकाय की स्थापना

एक स्पष्ट डाटा प्रणाली कानून तथा सुदृढ़ साइबर सुरक्षा तंत्र भारत की डिजिटल सेवा प्रणाली के लिए अपेक्षित है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

17. कानून के अलावा, भारत में 'सभी के लिए स्वास्थ्य के अधिकार' की पूर्ण प्राप्ति हेतु सामाजिक, वित्तीय और बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। परीक्षण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Besides legislation, the full realisation of the 'right to health for all' in India demands plugging of social, financial, and infrastructural gaps. Examine. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारतीय संविधान में अंतनिहित रूप से अनु॰ 21 के तहत गरिमा सहित जीवन के लिए स्वास्थ्य के अधिकार की घोषणा की गई है।

स्वास्थ्य के अधिकार के समक्ष चुनौतियाँ

सामाजिक

- स्वास्थ्य के प्रति सजग न रहना
(उदा॰) हाथ धोने की संस्कृति का न होना
WHO 40% से अधिक बिमारी रोग स्वच्छता के पालन से कम हो सकते है।

सामाजिक रुढ़िवादिता (महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं)

- जनजातीय लोगों तथा झाड़ फूंक पर बल देना
(उदा॰) साँप काटने पर अस्पताल जाने के बजाए झाड़ फूंक अपनाना

- स्वास्थ्य के प्रति (प्रतिक्रियात्मक रवैया)
(खराब होने के बाद देखना, बीमारी

से पहले ज्ञान और तैयारी जैसी अभिवृत्ति का न होना

वित्तीय समस्याएं
- Out of Pocket expend. का 60% से ज्यादा का होना
- स्वास्थ्य सेवाओं पर निजीकरण का प्रभुत्व (80% से ज्यादा नागरिक निजी स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता)
- रोजगार तथा Disposable Income में कम होना (स्वास्थ्य की तैयारियों के लिए बिल का अभाव होना
- पोषण युक्त खाद्यान्न तक पहुँच का अभाव (22% जनसंख्या अभी भी अत्यधिक गरीब)

बुनियादी समस्याएं
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की निम्न स्थिति
- बिजली, प्रयोगशाला, टेस्टिंग आदि के अभाव
- संस्थानीकृत डॉक्टरों का अभी भी अभाव

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

स्वास्थ्य अधिकार के प्रति हालिया उठाये गये कदम

- PM आयुष्मान रोजगार योजना (OOPE को कम करने के लिए)
- आंगनवाड़ी सहायता केंद्र (पोषण युक्त भोजन तथा टीकाकरण के लिए)
- मातृत्व लाभ योजना (Institutional Delivery को बढ़ावा देना)
- मिशन इंद्रधनुष (वैक्सीनेशन कार्यक्रम)

आगे की राह → स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार के हस्तक्षेप की जरूरत (COVID काल में उद्घोषित)

→ निजीकरण को संतुलित करने पर बल

(उदा० राजस्थान सरकार द्वारा Right to health के निजी अस्पतालों को शामिल करना)

स्वास्थ्य में निवेश के माध्यम से भारत अपनी उभरती मानव पूंजी में विकास कर तीव्र सामाजिक लाभ का फायदा उठा सकता है

18. विधायी समर्थन के बावजूद 'थर्ड जेंडर' को अभी तक भारतीय समाज में मान्यता नहीं मिली है। विश्लेषण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
The 'third gender' has not yet been engendered in the Indian society despite legislative nudge. Analyse. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

थर्ड जेंडर से आशय पुरुष और स्त्री के अलावा लिंग की एक और श्रेणी को संदर्भित करता है।

थर्ड जेंडर के लिए विधायी समर्थन

- ECI द्वारा वोटर कार्ड में थर्ड जेंडर का विकल्प देना
- थर्ड जेंडर के लिए सरकारी नीति (जैसे स्वप्रमाणित के माध्यम से थर्ड जेंडर)
- रोजगार / नियोजन में थर्ड जेंडर के साथ भेदभाव के विरुद्ध हर्जाने का प्रावधान
- स्वास्थ्य तक पहुँच को बढ़ावा देना

सामाजिक मान्यता न मिलने के कारण

- सामाजिक रूढ़िवादी सोच का होना
- थर्ड जेंडर के प्रति संवेदना जैसे मूल्यों का अभाव
- सरकारी नीतियों का सिर्फ कागजी स्तर पर प्रभाव → धरातल पर क्रियान्वयन संबंधी मुद्दे
- रोजगार/शिक्षा/स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों तक अभी भी पहुँच का अभाव
- थर्ड जेंडर के परिवार जनों द्वारा ही उनकी बातों को न सुना जाना
- सरकार से 'थर्ड जेंडर' के उत्थान के लिए विशिष्ट कोष का न होना
- थर्ड जेंडर संबंधी NGO's का भी अभाव होना

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidate must not write on this margin

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

सुधार के उपाय

- 'Role models' की सहायता से अभिवृत्ति परिवर्तन पर बल
- थर्ड जेंडर संबंधी नीतियों को न मानने पर दंडात्मक तथा कठोर सज़ा का प्रावधान
- सरकारी नियोजन तथा शिक्षा में आरक्षण को देना
  उदा. अनु. 15 तथा 16 में संशोधन की आवश्यकता

थर्ड जेंडर अन्य नागरिकों की तरह है अतः उनके मूल अधिकारों की रक्षा करना समाज तथा सरकार का प्रधान कर्तव्य है।

19. अन्य कारकों के अलावा, चीन और पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंधों ने भारत के लिए शंघाई सहयोग संगठन (SCO) से अपनी अपेक्षाओं को पूरा करना कठिन बना दिया है। विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Among other factors, strained ties with China and Pakistan make it difficult for India to fulfill its expectations from the Shanghai Cooperation Organisation (SCO). Discuss. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

शंघाई सहयोग संगठन चीन, रूस, पाकिस्तान भारत तथा अन्य मध्य एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन है।

SCO से संबंधित चुनौतियां

- सदस्यों के आपसी विवाद
  - उदा० भारत - चीन, भारत - पाकिस्तान } सीमा विवाद
- सदस्य देशों के बीच एकता की कमी
  - उदा० रूस - चीन - भारत
- भारत का SCO के विरोधी देशों के साथ भी गठबंधन
  - उदा० QUAD, Indo-Pacific

(6) SCO के मुद्दों में सदस्य आकांक्षाओं का न होना

(उदा) भारत – आतंकवाद पर ज़ोर

चीन, रूस → US हेजेमनी

पाकिस्तान – कश्मीर विवाद

(6) SCO में चीनी प्रभुत्व की स्थिति होना

हालांकि SCO के संबंध में कुछ सकारात्मक अवसर भी उपलब्ध है

→ आपसी विवादों के लिए मंच प्रदान करना

(उदा) भारत पाकिस्तान तथा चीन के लिए

- आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए

(उदा) भारत की मध्य एशिया के ऊर्जा स्रोतों तक पहुंच

- 'RATS' जैसे संगठन आतंकवाद की समस्याओं को हल करने में सक्षम

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidate must not write on this margin

आगे की राह

- भारत को रूस-यूक्रेन वार में मध्यस्थता का रोल निभाना SCO की प्राथमिकता में बना देना

बातचीत के माध्यम से सीमा विवाद मुद्दों को निपटाना

- आर्थिक एकीकरण पर जोर देना चाहिए
- सांस्कृतिक, peer to peer संपर्क पर बल

मध्य एशिया तथा दक्षिण एशिया की कनेक्टिविटी के लिए SCO एक प्रमुख मंच बन सकता है

0. संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकी (iCET) पर हाल ही में संपन्न पहल, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनकी साझेदारी में लंबे समय से प्रतीक्षित परिवर्तन का वादा करती है। परीक्षण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

The recently concluded initiative on Critical and Emerging Technology (iCET) between the United States and India promises a long overdue transformation of their partnership in the field of technology. Examine. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

US तथा भारत के बीच 'iCET' की साझेदारी दोनो देशों के बीच रणनीतिक स्थिति को एक अलग आयाम की तरफ ले जा रही है।

iCET का महत्व

- अमेरिकी नवाचार प्रौद्योगिकियों तक भारत की पहुँच स्थापित करना
- डिजिटलीकरण के संदर्भ में दोनो देशों के बीच समझौते
- परमाणु तथा नई तकनीकीय योजनाओं पर बल

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidate must not write on this margin

iCET के विभिन्न चुनौतियाँ

- भारत में डाटा कानून संबंधी चुनौतियाँ
- मजबूत डाटा सुरक्षा तंत्र का अभाव
- क्रिटिकल अवसंरचना के लिए वित्त का अभाव
- लोगों की नागरिकता का न होना
- तकनीकी विशेषज्ञता संबंधी समस्या
- प्रशासनिक संबंधी समस्या
- नियामक निकाय का अभाव

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

SPACE FOR ROUGH WORK